4.1

अध्याय – 4

भारतीय राजनीति में सोनिया गाँधी की भूमिका

4.1 सांसद के रूप में सोनिया गाँधी

4.2 नेता प्रतिपक्ष के रूप में सोनिया गाँधी

सांसद के रूप में सोनिया गाँधी

नेहरू–गाँधी परिवार की परम्परागत लोकसभा सीट उत्तरप्रदेश की अमेठी और रायबरेली रही हैं। जब–जब भी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से नेहरू गाँधी परिवार के किसी भी सदस्य ने लोकसभा चुनाव लड़ा है, वह इस क्षेत्र से जीतकर लोकसभा पहुँचा है। अमेठी एवं रायबरेली की जनता का गाँधी परिवार के प्रति विशेष लगाव रहा है, और इन दोनों क्षेत्रों की जनता ने हमेशा गाँधी परिवार से अपना रिश्ता निभाया है। गाँधी परिवार का भी यहाँ की जनता से वर्षों पुराना रिश्ता है। यह कोई नया रिश्ता नहीं है कि इसे सोनिया गाँधी ने कायम किया हो, यह सम्बन्ध तो करीब 50 वर्ष पुराना है।

फिरोज गाँधी, इंदिरा गाँधी और राजीव गाँधी यह तीनों गाँधी अमेठी और रायबरेली से ही प्रथम बार लोकसभा पहुँचे थे और बाद में इंदिरा गाँधी और राजीव गाँधी इन क्षेत्रों से निर्वाचित होकर देश के प्रधानमंत्री बने और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। आज सोनिया गाँधी का इन क्षेत्रों की जनता से वही लगाव और रिश्ता है जो इंदिरा गाँधी और राजीव गाँधी का हुआ करता था। सोनिया गाँधी ने भी अपनी सास और पति की परम्परा को कायम रखा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुये इन दोनों क्षेत्रों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंदिरा गाँधी का रायबरेली से बेटी का रिश्ता था जो उन्होंने अंतिम समय तक निभाया और अब सोनिया गाँधी का इस क्षेत्र से बहू का रिश्ता है जो सोनिया गाँधी ने बखूबी निभाया है। गाँधी परिवार का इन दोनों क्षेत्रों से विशेष लगाव रहा है। इसी लगाव के चलते कभी उन्होंने दूसरे अन्य क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की और यदि की भी तो जीत के बाद उस क्षेत्र की सीट से इस्तीफा दे दिया, परन्तु अपने क्षेत्र रायबरेली और अमेठी को कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तो सिर्फ एक ही नाम चलता है वह है गाँधी परिवार। गरीब, असहाय और निर्धनों को सहारा दिया है। 6 दिसम्बर, 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहाई जा रही थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह–जगह दंगे और उपद्रव हो रहे थे। एक समुदाय दूसरे समुदाय की

जान लेने पर तुला था। सरकार दंगों से परेशान थी परन्तु रायबरेली देश का एक ऐसा शहर था जिसमें उस दिन न तो कोई दंगा हुआ और न ही किसी प्रकार का उपद्रव। बाजार खुले थे, हिन्दु–मुस्लिम एक दूसरे से मिल रहे थे, एक–दूसरे के घर जा रहे थे, उनमें किसी भी बात को लेकर किसी प्रकार की विद्वेष भावना नहीं थी। इसका मुख्य कारण था गाँधी परिवार जिसने इस क्षेत्र में शांति सद्भाव बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई।

जून, 2008 को मैंने रायबरेली और अमेठी की यात्रा की। रायबरेली में मैंने जब सोनिया गाँधी की कार्य–शैली को लेकर जनता से बात की तो मैं अचंभित रह गया कि इतने बड़े लोकतंत्र और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष देश की सबसे शक्तिशाली महिला इतनी साधारण भी हो सकती है। यह वही सोनिया गाँधी है, जिसके बिना पूछे 10 जनपथ में हवा भी प्रवेश करने से कतराती है दूसरी और रायबरेली की जनता ने बताया कि हमारी नेता हमसे लगातार मिलने आती है। सदा बड़े–बूढ़ों को वही सम्मान देती है जो इंदिरा गाँधी और राजीव गाँधी दिया करते थे, सिर पर पल्लू हमेशा रायबरेली में रहता है और छोटी से छोटी समस्या भी हो तो उसका समाधान किये बिना रायबरेली से नहीं जाती। इंदिरा गाँधी की तरह सोनिया गाँधी भी क्षेत्र का समय–समय पर दौरा करती हैं एवं जनता की समस्याओं से स्वयं रूबरू होकर उसकी समस्याओं का समाधान करती हैं। जब किसी को दुखी देखती हैं तो स्वयं दुखी हो उठती हैं। वाकई सोनिया गाँधी, गाँधी परिवार की परंपरा का निर्वाहन कर इस क्षेत्र के लोगों को शांति और विकास के समस्त साधन प्रदान किये हैं। जनता सोनिया गाँधी के अलावा अन्य किसी प्रतिद्वन्दी को क्षेत्र में घुसने नहीं देतीं, सोनिया गाँधी समाज कल्याण और जनहित में सर्वोपरि हैं क्योंकि वही गरीबों, असहायों, निर्धनों और पीड़ितों की पीड़ा को समझ सकती हैं।

सन् 1999 में सोनिया गाँधी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते हुये पहला लोकसभा चुनाव गाँधी परिवार की राजीव गाँधी की सीट अमेठी से लड़ा। 1999 में सोनिया गाँधी पहली बार अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुँची। सोनिया गाँधी अमेठी में इस चुनाव से पहले कई बार आ चुकी थीं। राजीव गाँधी जब इस सीट से चुनाव लड़ते थे तो सोनिया गाँधी उनके चुनाव प्रचार के

लिये राजीव गाँधी के साथ आती थीं और इस क्षेत्र का दौरा करती थीं तथा मुस्करा कर कहती थीं – "पति जी को वोट दीजिएगा" जनता भी अपनी इस विदेशी बहू को देखने के लिये सड़कों पर आ जाती थी अतः सोनिया गाँधी के लिये यह क्षेत्र नया नहीं था वह यहाँ की डग–डग से वाकिफ थीं।

सन् 1999 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गाँधी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके प्रतिद्वंदी नहीं चाहते थे कि वह चुनाव जीत कर लोकसभा पहुँचे। उनके सामने कई समस्यायें पैदा करने की कोशिश की परन्तु उन्होंने सभी का डटकर मुकाबला किया और जीत हासिल की। शुरू में इस विदेशी बहू को भाषा की दिक्कत थी जिससे अमेठी के लोगों के साथ तालमेल बैठाने में परेशानियां होती थी परन्तु अमेठी की जनता ने अपनी बहू की परेशानी को समझकर इस समस्या का समाधान कर दिया। सन् 1991 में राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने सुखों को छोड़कर स्वयं कांटों के रास्ते पर चलना स्वीकार किया एवं परेशानियों से लड़ना सीखा। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गाँधी को भाजपा सरकार ने कई तरह से परेशान किया। राजग सरकार ने उनके खिलाफ सत्ता का दुरूपयोग कर उन पर अप्रत्यक्ष आरोप लगाये परन्तु वह अपने कर्तव्य से जरा भी विचलित नहीं हुईं और सफलता हासिल की।

प्रथम लोकसभा चुनाव (1999) अमेठी से उनके प्रतिद्वंद्वी रहे संजय सिंह ने सोनिया गाँधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। संजय सिंह अमेठी क्षेत्र के ही रहने वाले थे और वहाँ के प्रभावशाली लोगों में उनकी गिनती की जाती थी। लोग बताते हैं कि संजय सिंह क्षेत्र की जनता से जो कुछ कह दें वही होता था। संजय सिंह राजीव गाँधी के मित्र थे। संजय सिंह का नाम राजा के नाम की तरह चलता था। राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद अमेठी लोकसभा खाली हो गया क्योंकि सोनिया गाँधी ने शुरू में राजनीति में आने से साफ मना कर दिया था। संजय सिंह ने सत्ता के लालच में आकर अपने सम्बन्धों को भुलाकर भाजपा की सदस्यता ले ली।

सन् 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुये और अमेठी से सोनिया गाँधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो भाजपा ने संजय सिंह का भी अमेठी से पर्चा भरवा दिया। उसके बाद संजय सिंह ने अपनी पूरी ताकत के साथ सोनिया गाँधी

के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। भाजपा सरकार ने भी पूरी सुविधा प्रदान कर संजय सिंह को सोनिया गाँधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने दिया। एक ओर ताकतवर जमींदार मैदान में था तो दूसरी ओर हजारों मील दूर दिल्ली से आई विदेशी बहू मैदान में थी। भाजपा ने संजय सिंह को अनुचित साधनों का दुष्प्रयोग कर चुनाव जिताने की पूरी कोशिश की। राजा ने भी जनता से साम–दाम–दंड के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश की परन्तु वह नाकाम सिद्ध हुये। सन् 1999 को अमेठी की जनता ने राजा जमींदार को तीन लाख वोटों से हराकर विदेशी बहू को दिल्ली में राजीव गाँधी की तरह कुर्सी प्रदान कर लोकसभा पहुंचाया। जनता ने जिस तरह भाजपा का सफाया किया उससे भाजपा की परेशानियां और बढ़ गईं। सोनिया गाँधी ने अपनी जीत का पूरा श्रेय अमेठी क्षेत्र की जनता को दिया और अपने वायदे को दुहराया कि इस क्षेत्र के विकास के लिये मैं दिन–रात एक कर दूंगी। यहां कोई गरीब भूख से नहीं मरेगा उन्होंने अपना वायदा भी निभाया और इस क्षेत्र को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की एवं विकास में सहयोगी बनीं। सोनिया गाँधी ने अमेठी क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद पूरी ईमानदारी से इस क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

सन् 1999 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह संजय सिंह ने सोनिया गाँधी को परेशान करने का प्रयास किया। उसी तरह कर्नाटक बेल्लारी से सोनिया गाँधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही सुषमा स्वराज ने भी सोनिया गाँधी को कई तरह से परेशान करने के प्रयास किये।

सन् 1999 में सोनिया गाँधी ने पहली बार लोकसभा में आने के लिये दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ना स्वीकार किया। सोनिया गाँधी ने इसलिए ऐसा किया ताकि भाजपा उन्हें कमजोर न समझे। उन्होंने पहला नामांकन पत्र अमेठी लोकसभा से संजय सिंह के विरूद्ध भरा और दूसरा नामांकन बेल्लारी (कर्नाटक) से सुषमा स्वराज के विरूद्ध। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से भाजपा के दिग्गज सोनिया गाँधी के खिलाफ मैदान में थे। भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज ने बेल्लारी में सोनिया गाँधी पर आक्रामक प्रहार किये और अपना प्रचार कई तरीके से किया जिसमें 'देशी बेटी बनाम विदेशी बहू का नारा था' परन्तु सुषमा स्वराज का दुष्प्रचार काम न आया और

बेल्लारी की जनता ने उन्हें बहुमत न देकर विदेशी बहू को बहुमत देकर दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। सोनिया गाँधी ने लाखों वोटों के अन्तर से सुषमा स्वराज को हराकर उनकी बोलती बन्द कर दी। सोनिया गाँधी चूंकि अमेठी से भी जीती थी अतः उन्होंने बेल्लारी लोकसभा सीट से 20 अक्टूबर 1999 को इस्तीफा दे दिया और अपनी परम्परागत सीट अमेठी को संभाला।

सोनिया गाँधी ने अमेठी क्षेत्र के विकास के लिये लोकसभा में कई प्रश्न उठाये एवं इस क्षेत्र में नयी योजनाओं की शुरूआत की परंतु सोनिया गाँधी इस क्षेत्र के विकास को लेकर जिस तरह सोचती थीं उनकी वह सोच पूरी नहीं हो सकी कारण था भाजपा द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाना। उस समय केन्द्र में भाजपा की सरकार थी और अमेठी में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिये अपनी पूरी ताकत लगा दी थी परन्तु फिर भी जीत सोनिया गाँधी की हुई। भाजपा ने इसका बदला सोनिया गाँधी से लिया और इस क्षेत्र में केन्द्र से जो सहायता दी जानी चाहिए थी उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

भेदभावपूर्ण नीति का एक और मुख्य कारण था वह यह कि उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई। 1998–99 में कांग्रेस सत्ता से बाहर जरूर थी परन्तु विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी और विपक्ष की नेता स्वयं अमेठी की सांसद सोनिया गाँधी थी। सोनिया गाँधी ने भाजपा सरकार की जन विरोधी और देश विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया और संसद में उसके खिलाफ आवाज उठाई भाजपा सरकार के घोटालों को उजागर किया एवं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पेश किया। इस तरह से भाजपा सोनिया गाँधी से एवं उनके लोकसभा क्षेत्र अमेठी को सहायता देने में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने लगी।

सन् 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और अमेठी से सोनिया गाँधी ने अपने पुत्र राहुल गाँधी को प्रत्याशी बनाया और स्वयं रायबरेली से प्रत्याशी बनीं। जनता ने भी राहुल गाँधी को आर्शीवाद दिया और विजयी घोषित किया जो कार्य भाजपा की भेदभावपूर्ण नीति के कारण अमेठी में रह गये थे उन कार्यों को सोनिया गाँधी ने यू.पी.ए. सरकार के द्वारा राहुल गाँधी के माध्यम से पूर्ण करवाये।

सन् 2004 में सत्ता में भारी परिवर्तन भी हुआ। भाजपा के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में वापिस लौटी। यह ऐसा समय था जब सोनिया गाँधी इस कांग्रेस सरकार की सर्वोसर्वा थीं। सांसद के साथ–ही–साथ वह लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद को सुशोभित तो कर ही रही थीं साथ ही यूपीए सरकार की अध्यक्ष भी थीं अर्थात वह इस बार सर्वशक्तिशाली थीं और अब उनके साथ 1999 जैसा भेदभाव भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि अब की बार उनकी ही पार्टी की सरकार थी।

अतः सोनिया गाँधी ने रायबरेली की जनता से चुनाव के समय जो वायदा किया उससे कहीं ज्यादा इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में गरीबी–अमीरी, हिन्दू–मुस्लिम का भेदभाव मिटा कर सबको समानता का अवसर प्रदान किया जिससे इस क्षेत्र की जनता अपना पूर्ण विकास कर सके उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों तक के कठिन से कठिन कार्य किये। उनके विपक्षी भी अब सोनिया गाँधी के गुणगान करने लगे और कहने लगे कि जिस तरह रायबरेली क्षेत्र का विकास सोनिया गाँधी ने किया है उससे उनकी मंशा साफ है। जन कल्याण और दुखियों के दुख दूर करना।

सोनिया गाँधी ने रायबरेली क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिये के विकास हेतु योगदान दिया। डलमऊ रायबरेली से 32 कि.मी. दूर स्थित गंगा के किनारे बसा ऐतिहासिक नगर है। यहां प्रतिवर्ष कई लाख लोग आते हैं। सोनिया गाँधी के प्रयासों से केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन की अथाह संभावनाओं के लिये 1.83 करोड़ रूपये दिये जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

सोनिया गाँधी ने 1998 में रायबरेली में इंदिरा गाँधी मेमोरियल जैविक उद्यान का निर्माण किया। उन्हीं के प्रयासों से उद्यान विकास हेतु 40.90 लाख रूपये खर्च किये जिससे स्वर्गीय राजीव गाँधी का सपना पूरा हो गया।

सांसद सोनिया गाँधी ने इस क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्र से कई करोड़ रूपये मांगे जिसकी उन्हें स्वीकृति भी मिल गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से करोड़ों रूपयों के कार्य हुये जिनमें जिला निर्योग्यता पुनर्वास केन्द्र, नगर पंचायत मुसाफिरखाना, जनपद–सुलतानपुर में

मौलाना आजाद सद्भाव केन्द्र की स्थापना, मदरसा फातिमा जहरा पुस्तकालय के लिये अनुदान एवं अन्य विकास कार्यों के लिये करोड़ों की राशि आवंटित करवाई।

रेल मंत्रालय – जीवन रेखा एक्सप्रेस :

राजीव गाँधी फाउण्डेशन के तत्वाधान में इम्पेक्ट इंडिया फाउण्डेशन एवं भारतीय रेल के सहयोग से ग्रामीण इलाकों में दूर–दराज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीवन रेखा एक्सप्रेस का संचालन किया गया। यह पटरियों पर चलता–फिरता ऐसा अस्पताल है जिसमें छोटे से मर्ज से लेकर बड़े से बड़ा आपरेशन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सांसद सोनिया गाँधी के प्रयासों से ग्रामीण जनता की बेहद मांग पर ऊंचाहार एवं बछरावां रेल्वे स्टेशनों पर इस ट्रेन का आवागमन दो महीनों तक किया गया। यह चिकित्सा सुविधा ग्रामीण जनता को बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई गई। गरीब जनता ने सांसद सोनिया गाँधी की इस पहल का स्वागत किया।[1]

रेल कोच फैक्ट्री :

सांसद सोनिया गाँधी के अथक प्रयासों से केन्द्रीय रेल मंत्रालय ने रायबरेली जिले में एक नए रेल कोच फेक्ट्री की स्थापना हेतु अपनी स्वीकृति दी। इस प्रोजेक्ट के तहत अनुमानतः 1200 करोड़ रूपये का निवेश किया जाना था किंतु उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री मायावती ने भेदभावपूर्ण नीति के तहत रेल कोच फेक्ट्री हेतु केन्द्र सरकार को दी जाने वाली जमीन को अचानक वापिस ले लिया। जिस पर सांसद सोनिया गाँधी ने 14 अक्टूबर, 2008 को आपत्ति दर्ज करायी किंतु मायावती की जनता विरोधी नीति के कारण जनता को गुमराह करते हुये कहा कि जो जमीन रेल कोच फेक्ट्री हेतु दी जा रही थी उस पर किसानों ने अपना विरोध जताया जिससे यह जमीन फेक्ट्री हेतु नहीं दी जायेगी। किंतु जब रायबरेली क्षेत्र के किसानों को मायावती की इस झूठ का पता चला तो किसानों ने स्पष्ट कहा कि हम अपनी जमीन रेल कोच फेक्ट्री को देना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर

वर्तमान मायावती सरकार, इन दोनों सरकारों ने सोनिया गाँधी के क्षेत्र रायबरेली के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुये जनता को गुमराह किया है। यदि यह फेक्ट्री शुरू हुई तो इसमें करीब 1500 कोच हर हर वर्ष बनाये जायेंगे तथा इस फेक्ट्री की स्थापना से क्षेत्र की करीब 15 से 20 हजार जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय :

भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ई–गर्वरनेंस विभाग, "राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क" प्रोजेक्ट रायबरेली तथा सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ खास लेकर आई है। यह सब सोनिया गाँधी के प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर द्वारा रायबरेली जिले में आई.सी.टी. द्वारा सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य शुरू किये गये।

एन.आई.सी. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा आम नागरिकों, व्यवसायियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा सरकार की मुश्किलों को कम्प्यूटर, इंटरनेट, एकल विंडो सिस्टम आदि को बढ़ावा देकर कम करने का प्रयास कर रही है।

सांसद सोनिया गाँधी ने इस क्षेत्र के किसानों का विशेष ध्यान रखकर वेब आधारित भूमि अभिलेखन (रिकार्ड) द्वारा जिले में भूमि का रिकार्ड इंटरनेट पर रखा जाएगा जिसका लाभ भूमिपति, किसान, बैंकों तथा न्याय विभाग को मिलेगा। साथ ही आम जनता अपनी जमीन संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेगी।

स्वर प्रतिक्रिया तंत्र (Voice Response System) :

सोनिया गाँधी ने इस व्यवस्था द्वारा रायबरेली के दूर–दराज के बृहद लोगों की कठिनाईयों को समाप्त करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पेंशन धारक (जैसे विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था आदि) फोन द्वारा IVRS (आई.व्ही.आर.एस.) सिस्टम पर डायल कर अपने पेंशन, बीमा, चेक, इसका नम्बर तथा राशि के संबंध में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धों, विकलांगों तथा महिलाओं के लिये यह योजना वरदान साबित हुई। यह योजना पूरे

देश में अपने–आप में अलग है और इसके संचालन का श्रेय सांसद सोनिया गाँधी को जाता है जिन्होंने जागरूकता के लिये यह पहल की।

भारतीय टेलीफोन निगम (ITI) :

रायबरेली की विकास यात्रा में टेलीकाम उद्योग भी अपना योगदान दे रहा है। सोनिया गाँधी ने रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरप्रदेश की I.T.I. यूनिटों को पुनर्जीवित करने हेतु 100 करोड़ से भी अधिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। 44 करोड़ रूपयों के खर्च से रायबरेली में 3 लाख लाइनों की क्षमता की सुविधा आई.टी.आई. (ITI) द्वारा उपलब्ध कराई गई।

रायबरेली में जी.एस.एम. (GSM) के निर्माण से लगभग 130 करोड़ का सहयोग दिया गया।

एल्फीयोन की अमेरिकी तकनीक के माध्यम से जीपोन पार्टी का निर्माण भी किया जाएगा।

डाक विभाग द्वारा रायबरेली में विकास के लिए पहल :

रायबरेली में 10.15 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में डाकतार का विस्तार है। 300 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में पत्र–पेटिका की व्यवस्था की गयी। 8 मई, 2005 से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थानान्तरण सेवा की सुविधा बढ़ाकर महाराजगंज पोस्ट ऑफिस तक कर दी गई। यह सौर ऊर्जा पर आधारित है इससे यहाँ के निवासियों को नई तकनीक जानने व इस्तेमाल करने का अवसर मिला है।

राज्य बागवानी मिशन :

सांसद सोनिया गाँधी की पहल पर केन्द्र सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन का गठन किया है जिसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्य बागवानी मिशनों को 10वें प्लान के शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता तथा 85 प्रतिशत ग्यारहवें प्लान में उपलब्ध कराये जायेंगे। रायबरेली में बागबानी की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने भी इस मिशन में रायबरेली को सम्मिलित किया है जिसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा 53 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं। यह राशि जिले को बांट

दी गई। इस वित्तीय वर्ष में करीब 124 करोड़ के प्रावधान में रायबरेली को 4 करोड़ की राशि आवंटित की गई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा रायबरेली में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा पिछले वर्षों में कृषि विज्ञान से सम्बंधित 108 फ्रंट लाइन डिमांस्ट्रेशन (Frontline Demonstration) के तहत 6565 किसान लाभान्वित हुए। दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में 7 नवंबर, 2005 को 2000 लीटर की क्षमता वाले दो दुग्ध शीतगृह स्थापित किये गये। यहाँ करीब 685 दुग्ध उत्पादक, 38 दुग्ध उत्पादक–संस्थानों पर दूध एकत्र करते हैं।

सांसद सोनिया गाँधी ने चाहे किसान, विद्यार्थी, कर्मचारी वर्ग हो या व्यवसायी सभी के लिये कुछ न कुछ किया है। उन्होंने गरीब जनता एवं बेरोजगारों का विशेष ध्यान रखकर उनको रोजगार के सभी अवसर प्रदान किये हैं।[2]

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय :

कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अन्तर्गत गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रायबरेली में सी.एस.आर. (CSR) कार्यक्रमों के तहत यहां एक करोड़ रूपये का निवेश करने की योजना बनाई है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया इस पर 30 लाख खर्च होने का अनुमान है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय :

सन् 2004 के पहले 28.72 लाख की जनसंख्या वाले रायबरेली संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत गंभीर थी। सोनिया गाँधी ने सांसद बनने के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से "आपात्कालीन सुविधाओं को बढ़ाने तथा उसे मजबूती प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता" प्रोजेक्ट के तहत सरकारी अस्पताल को 1 करोड़ 50 लाख रूपये की सहायता मांगी जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह राशि प्रदान की। रायबरेली में विकलांग व्यक्तियों के लिए राजस्थान की एन.जी.ओ. तथा आर.जी.सी.टी. के माध्यम से जायलपुर फुट मुफ्त उपलब्ध कराये गये।

ग्रामीण विकास मंत्रालय :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005, सोनिया गाँधी की पहल पर भारत सरकार ने 5 सितम्बर 2005 को इस अधिनियम को अधिसूचित किया जिसके अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों की आजीविका की सुरक्षा हेतु प्रत्येक ऐसे गृह को जिसके वयस्क सदस्य, अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटी कृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर वर्धित करने तथा उससे संसप्त या उसके आनुषांगिक विषयों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 3,28,641 आवेदन पत्रों का पंजीकरण कराया गया जिसमें से 3,15,921 प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये जा चुके हैं।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :

इस योजना के तहत रायबरेली क्षेत्र हेतु दो प्रस्तावों में 14.89 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई जिसमें से 3 करोड़ एल.ए.बी.एस. तथा 11.89 करोड़ बी.ए.आई.एफ. के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) की निगरानी में खर्च किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत आम जनता को मध्यवर्गीय रोजगार प्रदान किये जा रहे हैं। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना तथा 18–35 वर्ग के 7500 से भी अधिक लोगों का विषय–विशेष पर रोजगार देना है। जबकि बी.ए.आई.एफ. के अंतर्गत करीब 4000 ग्रामीणों से वर्ष 2008 के अंत तक रोजगार देना है।

नवम्बर, 2006 तक रायबरेली में स्वरोजगार समूह को 7.71 करोड़ रूपये का ऋण एवं 4.21 करोड़ का अनुदान एवं व्यक्तिगत स्वरोजगारों को 2.47 करोड़ ऋण एवं 1.20 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया जिसमें अनुसूचित जाति–जनजाति के व्यक्तियों को 6.08 करोड़ का ऋण, महिलाओं को 2.55 करोड़ का ऋण एवं अनुदान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को 1.44 लाख रूपये का ऋण एवं 75000 रूपये का अनुदान शामिल है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना :

रायबरेली में ग्रामीण सड़क योजना के लिए ग्रामीण इंजिनीयरिंग सेवा को भारत सरकार द्वारा 10.02 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई जिसका उपयोग 39.40 कि.मी. सड़क निर्माण के लिये किया गया।

राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अंतर्गत 15 करोड़ रूपये प्राप्त हुये इसमें से 11.25 करोड़ खर्च किया जा चुका है। 14 सम्पर्क मार्गों (28.15 कि.मी.) के निर्माण के लिये कुल 4.03 करोड़ उन्मुक्त किया गया। इसके अलावा 23 बेसिक कन्या विद्यालयों के निर्माण में 1.46 करोड़ पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु 36.95 लाख, 133 मध्यम नलकूप एवं 5 बांध बनाने के लिए 3.10 करोड़ लघु सिंचाई के लिये 193 मध्यम नलकूप 1 बांध हेतु 1.60 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार ने दी। सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत 2004–2005 में 60 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण। वनीकरण हेतु रायबरेली 40.39 लाख की राशि मिली। विद्युतीकरण हेतु 1.78 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

इंदिरा आवास योजना :

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 3306 आवासों का निर्माण किया गया। 2006–07 तक 2500 आवासों का निर्माण किया जा चुका है और गरीब एवं पिछड़ों को आवंटित भी कर दिये गये। 6.88 करोड़ की राशि इस योजना पर खर्च होना है।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत करीब 4609 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में निवास कर रहे 1773 गांवों को बिजली प्रदान की जाएगी। 30 मार्च, 2005 को रायबरेली में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ सांसद सोनिया गाँधी के हाथों हुआ। 6 दिसम्बर, 2006 को सोनिया गाँधी द्वारा एन.टी.पी.टी. की फिरोज गाँधी ऊंचाहार परियोजना की 210 मेगावाट की पांचवी इकाई का उद्घाटन एवं इस इकाई से परियोजना की कुल क्षमता 1050 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया गया।[3]

सांसद सोनिया गाँधी ने इसके अलावा अरबों रूपये केन्द्र सरकार से रायबरेली क्षेत्र के लिये मांगे और केन्द्र सरकार ने यह राशि प्रदान भी कर दी। सोनिया गाँधी के मई 2004 में रायबरेली से सांसद बनने के बाद उन्होंने रायबरेली क्षेत्र के लोगों के विश्वासानुसार कार्य किये और आज पूरे रायबरेली क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। मैंने पाया कि शहर से लेकर गांव तक और गरीब से लेकर अमीर वर्ग का व्यक्ति भी अपनी सांसद सोनिया गाँधी का गुणगान कर रहा है। उन्होंने जो वायदा चुनाव के समय किया तथा उससे कहीं अधिक वह अपने वायदे

पर खरी उतरीं और उन्होंने रायबरेली को विकास के माध्यम से उत्तरप्रदेश के महानगरों की श्रेणी में ला दिया है जो सुविधा व्यक्ति को उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं मिलेगी वह रायबरेली में आसानी से मिल जायेगी सांसद सोनिया गाँधी ने रायबरेली क्षेत्र के विकास के लिये हरसंभव प्रयास किया।

केन्द्र सरकार ने जो राशि रायबरेली क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार को दी उस राशि का उत्तरप्रदेश सरकार ने भेदभाव पूर्ण नीति के चलते गलत उपयोग किया परन्तु उसके बावजूद भी सांसद सोनिया गाँधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने हार नहीं मानी और वह लगातार रायबरेली के विकास के लिये केन्द्र सरकार से योजनायें और करोड़ों–अरबों रूपये लाती रहीं। पहले मुलायम सिंह यादव रायबरेली के विकास में रोड़ा बने और फिर मायावती परन्तु इन दोनों के भेदभाव पूर्ण नीति के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने कुछ योजनाओं पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हुए विकास कार्य किये।

सोनिया गाँधी हमेशा विकास और समाज कल्याण को महत्व देती है। चाहे राष्ट्र का विकास हो प्रदेश का या फिर जिले का वह हमेशा आगे बढ़ने की बात करती रही हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को कभी भी हावी नहीं होने दिया यदि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उन्होंने उस पर सीधी कार्यवाही की चाहे नटवरसिंह की बात हो या अन्य किसी की उन्होंने ऐसे किसी भी नेता को बढ़ावा नहीं दिया जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हो।

सोनिया गाँधी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत करोड़ों रूपये केन्द्र सरकार से दिलाये ताकि रायबरेली की सड़कें अच्छी हो सके परंतु इन सड़कों के निर्माण हेतु जिन ठेकेदारों ने ठेका लिया और सड़कों का निर्माण करवाया उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई जब क्षेत्र की जनता ने सोनिया गाँधी से शिकायत की कि जिन सड़कों का निर्माण हुआ है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है तो सोनिया गाँधी ने पहले तो राज्य सरकार से इसकी शिकायत की परंतु राज्य सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि सड़क निर्माण के ठेकेदारों ने करोड़ों रूपये राज्य सरकार के मंत्रियों को भी खिलाये थे अंत में सांसद सोनिया गाँधी ने इस भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ता की जांच की मांग हेतु केन्द्र सरकार से शिकायत की। केन्द्र सरकार ने शीघ्र निर्णय लेते हुए सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराई जिसमें

गुणवत्ता की कमी पाई गयी। 15 ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज कराकर सरकार ने उन पर सख्त कार्यवाही की।

उत्तरप्रदेश सरकार के दो मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और मायावती ने जितना विकास कार्य अपने मुख्यमंत्रित्व काल में करवाया उससे कहीं ज्यादा विकास रायबरेली की सांसद सोनिया गाँधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अकेले की दम पर करवा चुकी हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विकास में बाधा बने तो उन्होंने केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र के विकास में सीधी पहल करने का अनुरोध किया जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली मात्र ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां व्यक्ति शिक्षित, रोजगार, स्वस्थ्य और चिंतामुक्त होने के साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी रहा है। रायबरेली शांति और अमन का क्षेत्र है। यहां की जनता पूर्ण शिक्षित है जो अज्ञानता का रास्ता छोड़ प्रकाश की ओर अपना कदम बड़ा रही है। जिसका श्रेय सांसद सोनिया गाँधी को जाता है।

मैंने रायबरेली क्षेत्र के लगभग 1500 लोगों से बात की जिसमें व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षित, अशिक्षित, युवा वृद्ध और विपक्षी दल के लोग शामिल थे। मैंने प्रश्न किया कि जबसे सोनिया गाँधी रायबरेली की सांसद बनी हैं तब से इस क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों में क्या बदलाव आया है? तब एक ही स्वर में उत्तर मिला कि विकास, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग, संचार, कृषि, पानी, कानून व्यवस्था और भाईचारे का क्षेत्र की जनता सोनिया गाँधी से उसी तरह खुश हैं जिस तरह 1980 के दशक में इंदिरा गाँधी और राजीव गाँधी से खुश रहा करती थीं परंतु उस समय इस क्षेत्र का विकास कम हुआ था सोनिया जी के आने से अब इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। सोनिया गाँधी सुरक्षा के कारणों से दिल्ली में रहते हुए भी जनता से सीधे संपर्क में रहती हैं प्रत्येक माह क्षेत्र के दौरे पर रायबरेली आकर जनता की समस्याओं से स्वयं रूबरू होती हैं।

सांसद सोनिया गाँधी ने जो विकास अमेठी और रायबरेली में किया उसका मुकाबला पूरे देश की कोई भी पार्टी का सांसद नहीं कर सकता। समाजहित व समाजकल्याण ही उनका मात्र उद्देश्य है।

4.2

नेता प्रतिपक्ष के रूप में सोनिया गाँधी

14 मार्च, 1998 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गाँधी ने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन को नियमित एवं सुनियोजित किया। 1998 में सोनिया गाँधी संसद सदस्य भी नहीं थीं जिससे वह कांग्रेस संसदीय दल की नेता बन सके इसके लिए कांग्रेस संसदीय दल के संविधान में यह संशोधन कराया गया कि कोई भी पार्टी नेता संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना भी इस संसदीय संस्था के लिए चुना जा सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष को कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव पास कर कांग्रेस संसदीय दल के नेता के साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी प्रदान की। सोनिया गाँधी ने इसे स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने सोनिया गाँधी की मदद के लिए 50 विशेषज्ञों की सूची बनाई जो चुनाव संबधी सुधार, संसद की कार्यवाहियों की जानकारी एवं प्रश्न तैयार कर विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण की प्रक्रिया और विदेश नीति जैसे विषयों की जानकारी देते थे। जिस समय सोनिया गाँधी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी उस समय वह बिलकुल अन्जान और सत्ता पक्ष के नेताओं से अपरिचित थीं। सोनिया गाँधी के लिए यह सबसे कठिन समय था कि वह सत्ता पक्ष राजग द्वारा किए जा रहे जन विरोधी कार्यों के प्रति किस तरीके से संसद में अपना विरोध दर्ज करेगी यह महत्वपूर्ण पक्ष था। राजग सरकार के कई मंत्रियों ने तो उनकी मजाक तक उड़ाई और कहा कि वह संसद के बारे में कुछ जानती ही नहीं परंतु 1999 में बाजपेयी सरकार को अल्पमत में लाने के बाद सत्ता पक्ष को सोनिया गाँधी की राजनैतिक कौशलता का एहसास हो गया और उनसे भय लगने लगा कि कहीं यह महिला राजग सरकार के लिये संकट पैदा न कर दे हुआ भी यही जिन लोगों ने सोनिया गाँधी को राजनीति का अनाड़ी कहा उन्हीं को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा 2004 में इसी कथित अनाड़ी महिला ने अकेले के दम पर राजग को सत्ता से बेदखल कर दिया।

सोनिया गाँधी ने समकालीन मुद्दो के बारे में निर्णय के लिये व्यापक प्रबंध किये उन्होंने पार्टी में बहुत सी समितियां बना दीं। राजनीतिक मामलों की समिति, शोध व संदर्भ समिति एवं विधायी मामलों की समिति।

सन् 1999 में संसद पहुंचने के बाद सोनिया गाँधी के लिए संसद का प्रतिदिन–एक नई चुनौती था क्योंकि उनका संकोची स्वभाव उन्हें कम बोलने देता था। संसद में सांसदों की नजरें सोनिया गाँधी पर टिकी रहती थीं।

प्रतिपक्ष की नेता का पद हासिल करने के बाद सोनिया गाँधी से कांग्रेसियों को यह आशा थी कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों, जैसे मुलायम सिंह यादव, चन्द्रशेखर, शरद पवार, मायावती, पी.ए.संगमा जैसे नेताओं के साथ चर्चायें करती रहेंगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुले आम सोनिया गाँधी के संकोची स्वभाव को दोषी माना और कहा कि वे विपक्षी दलों को अपने पक्ष में नहीं कर पायेंगी।

सन् 1999 में कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सोनिया गाँधी संसद भवन में सामने खड़े होकर उनका नेतृत्व करें परंतु सोनिया गाँधी के लिए अभी यह आसान काम नहीं था। सोनिया गाँधी समझती थीं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह स्वाभाविक है, उन्होंने अपने सहयोगियों को याद दिलाया कि किस तरह संसद में अपने पहले वर्ष सन् 1981–82 में राजीव जी एक भी भाषण नहीं दे पाये थे इसके बावजूद भी सोनिया गाँधी संसद के लिए दिन प्रतिदिन अनुभवी बनती जा रही थी। 29 अक्टूबर, 1999 को सोनिया गाँधी ने लोकसभा में सांसद के रूप में अपना भाषण दिया इसके पहले वह पांच बार बोल चुकी थीं। 1999 में सोनिया गाँधी कर्नाटक और अमेठी दोनों क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव लड़ी थीं और दोनों क्षेत्रों से उनकी विजय हुई। भाजपा की नेता सुषमा स्वराज ने सोनिया गाँधी को कर्नाटक (बेल्लारी) सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी जिसे सोनिया गाँधी ने स्वीकार किया सुषमा स्वराज ने "देशी बेटी बनाम विदेशी बहू" के नाम पर चुनाव लड़ा किन्तु बेल्लारी की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों क्षेत्रों से जीतने के बाद सोनिया गाँधी ने बेल्लारी सीट से इस्तीफा दे दिया।[4]

सोनिया गाँधी 29 अक्टूबर, 1999 को सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में पूरी तैयारी के साथ आईं जैसे ही सोनिया गाँधी अपना भाषण पढ़ने के

लिए खड़ी हुईं पूरे सदन में सीटियाँ बजने लगीं, उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार पर चुटकी लेकर की और कहा– "मैं सरकार को बधाई देती हूँ कि इसने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ा। सदन में सभी ने देखा कि भावुक सोनिया गाँधी बोफोर्स मामले में सरकार की कार्यवाही की आलोचना कर रही थीं। वे रोष में थीं क्योंकि भाजपा सरकार के इशारे पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने एक आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें स्व. राजीव गाँधी का नाम प्रमुख अभियुक्त के रूप में रखा था उन्होंने कहा कि – "इस सरकार के कार्य विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध की श्रेणी में आते हैं।" उन्होंने कहा कि – "बोफोर्स काण्ड की जांच जारी रहना चाहिए परंतु हम यह सहन नहीं कर सकते कि किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाया जाये जो निर्दोष है जो यहाँ पर अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं है।" सोनिया गाँधी का दुखी होना स्वाभाविक था वह बोफोर्स की जांच बंद नहीं करवाना चाहती थीं और न ही किसी का बचाव करना चाहती थीं उनका तो मात्र इतना कहना था कि – "जो व्यक्ति अब है ही नहीं उसे मुख्य अभियुक्त बनाने से सरकार को क्या फायदा होगा जबकि राजीव गाँधी निर्दोष थे। भाजपा का यह घृणास्पद कार्य बदले की भावना का था।"

संसद भवन में सोनिया गाँधी की इस दलील का भाजपा–राजग पर कोई असर नहीं पड़ा बाजपेयी ने बोफोर्स के आरोप पत्र से राजीव गाँधी का नाम हटाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। बोफोर्स का यह मामला सोनिया गाँधी और उनके सहयोगी सांसदों को आंदोलित करता रहा। सोनिया गाँधी के इस भाषण ने पार्टी सांसदों पर गहरा प्रभाव डाला। सांसदों ने अब एक ऐसी सोनिया गाँधी को देखा जो बोफोर्स प्रकरण की संवेदनशीलता के बावजूद इसकी जांच के बारे में बेझिझक बोल रही थी। सबको युवा राजीव गाँधी की यादें ताजा हो गईं जो कांग्रेसी सांसद सोनिया गाँधी में कमियां ढूढ़ते थे वे अब सब नजर अंदाज कर उन्हें अपने नेता के रूप में सहर्ष स्वीकार कर रहे थे।

20 दिसम्बर, 1999 को सोनिया गाँधी ने अपने अभिभाषण में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने के सरकार के इरादे का उल्लेख किया, परंतु सरकार इस आरक्षण के पक्ष में नहीं थी उन्होंने कहा कि – मैं यह जानना

चाहती हूँ कि वास्तव में सरकार का इरादा इस आरक्षण को लेकर क्या है ? सोनिया गाँधी ने महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में याद दिलाया। सोनिया गाँधी द्वारा इस आरक्षण की मांग का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व सांसद मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि – किसी भी कीमत पर महिला आरक्षण बिल सदन में लाने की जरूरत नहीं है। सोनिया गाँधी ने कहा कि – यदि सरकार यह बिल पेश नहीं करती तो कांग्रेस सरकार आने पर यह बिल पास कर दिया जायेगा। हुआ भी यही जब भाजपा ने इस आरक्षण को लागू नहीं किया तो 2004 में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद सोनिया गाँधी की इस मांग को पूरा करने की मंशा से महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया जो संसद में विचाराधीन है। महिलाओं में ऊर्जा का संचार किया। सोनिया गाँधी ने कांग्रेस में पार्टी स्तर पर भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।[5]

25 अप्रैल, 2000 को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सोनिया गाँधी ने संसद में कथित रूप से जन विरोधी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जन विरोधी कार्यप्रणाली को लेकर अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि – इस राजग (भाजपा) सरकार के सत्ता में आने के बाद से इसके द्वारा किए गए गलत कार्यों से पूरा देश पीड़ित है किसान और गरीब इस सरकार द्वारा त्रस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को सौंपा गया एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करना है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का सार ही हमारी धर्म निरपेक्षता है। धर्म निरपेक्षता ही इस सदी की परिभाषा है। धर्म निरपेक्षता राष्ट्र का मूल आधार है। इस धर्म निरपेक्षता पर संघ परिवार (जो भाजपा सरकार का मूलतत्व है) द्वारा बार–बार प्रहार किए गए हैं उन्होंने कहा कि संघ द्वारा धर्मनिरपेक्षता पर किए गए हमलों के विपरीत मैं इस देश को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमारे महान राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता की परम्पराओं को सुरक्षित करने के लिए अपना सदियों पुराना संघर्ष जारी रखेगी और हम उन सभी शक्तियों का मुकाबला करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी राष्ट्रीयता के आवश्यक

सिद्धांतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। धर्म निरपेक्षता मंत्रीपद एवं सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है।

सन् 2000 में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गाँधी के लिए संसद में मुख्य मुद्दे और भी थे परंतु कांग्रेस सरकार के 1996 में सत्ता से हटते समय जो विकास दर लगभग 8 प्रतिशत थी वह घटकर 1999 में 6 प्रतिशत से भी कम हो गई थी। यह गरीबों के प्रति सरकार की कमजोर नीतियां थीं जिसे सोनिया गाँधी ने मुख्य मुद्दा बनाया।

भाजपा सरकार के दौरान कृषि क्षेत्र जो भारत की समृद्धि का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व था उसका भी ह्रास हुआ। कृषि उत्पादन और खाद्य उत्पादन भी घटा। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को लेकर भी सरकार के सामने चिंता प्रकट की और तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी नीतियाँ किसान विरोधी हैं।

सोनिया गाँधी ने विपक्ष की नेता होने के कारण समय–समय पर अपनी भूमिका का निर्वाहन करते हुए सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया एवं सरकार को गरीबों के हित और रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने हेतु दबाव डाला क्योंकि राजग सरकार में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में गिरावट आयी थी। इसके साथ ही 1996 तक कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में भी 1996 के बाद धीमी गति आई। जवाहर रोजगार योाजना, रोजगार आश्वासन योजना, स्वर्ण जयंती योजना, ग्राम स्वराज योजना, नेहरू शहरी स्वरोजगार योजना, पनधारा और मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना और पेयजल योजना सभी में 1998 से 2000 तक तीव्र गिरावट आई। सोनिया गाँधी ने 25 अप्रैल, 2000 को संसद में कहा कि – मुझे यह प्रतीत होता है कि इस सरकार की रूचि जरूरत मंदों की वास्तविक चिंताओं के बजाय वर्तमान कार्यक्रमों के नाम बदलने और पहले से चल रहे कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने में अधिक है। राजग सरकार के दौरान पिछले वर्षों में इंदिरा गाँधी के गरीबी हटाओ कार्यक्रम से आखिरी कांग्रेस सरकार तक गरीबी का अनुपात आधा कम हो गया था और पिछले वर्षों (1998–2000) में कमजोर वर्गों की हालत

में कम सुधार हुआ था। राजग सरकार ने गरीबी पर प्रहार करने की बजाय वास्तव में गरीबों पर प्रहार किए। 25 अगस्त, 2000 को तीन नये राज्यों उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना पर सोनिया गाँधी ने राजग को बधाई भी दी।[6]

नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी ने 22 नवंबर, 2000 को राजग सरकार पर प्रहार करते हुये संसद में कहा कि – छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सूखे की चपेट में हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के राज्य बाढ़ से बर्बाद हो गए, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में चाय और रबर बागान का उद्योग पिछड़ रहा है।

कृषि की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुये नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि – कृषि संबंधी योजना परिव्यय को पिछले वर्षों के मुकाबले 500 करोड़ रूपये घटा दिये गये, पशु पालन में यह परिव्यय 60 करोड़ रूपये घटा दिये एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट का जो प्रावधान किया गया उसमें से भी 100 करोड़ रूपये घटा दिये। सोनिया गाँधी ने कहा कि – राष्ट्रव्यापी फसल बीमा व्यवहार्य तथा आवश्यक है। दुर्भाग्य है कि इसके लिए राजग सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया।[7]

संसद में नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गाँधी ने अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वाहन किया और समय–समय पर सरकार द्वारा जो जनहित विरोधी निर्णय लिये गये उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने राजनीति में आने के बाद ही अपना लक्ष्य स्पष्ट किया था कि गलत निर्णयों को बर्दास्त नहीं करूंगी चाहे वह निर्णय कांग्रेस सरकार द्वारा ही क्यों न लिये गये हों।

ऐसा नहीं कि प्रतिपक्ष की नेता होने के कारण सोनिया गाँधी ने राजग की सभी नीतियों का विरोध किया हो उन्होंने उनके द्वारा लिये गये जन हितेषी निर्णयों का स्वागत भी किया और प्रधानमंत्री बाजपेयी को बधाई भी दी। 19 अप्रैल, 2001 को उन्होंने संसद में कहा कि – हम सबके लिए गर्व की बात है कि जी.एस.एल.वी. उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन हो गया। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अग्रणी पंक्ति में आ जाएगा और सूचना तथा संचार क्रांति में पूर्ण

भागीदारी का भरपूर अवसर मिलेगा। जी.एस.एल.वी. उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन पिछली सरकारों (कांग्रेस) द्वारा बनाई गई व्यापक कार्य योजना की पराकाष्ठा है। पहला एस.एल.वी. का प्रमोचन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था और इसके बाद पी.एस.एल.वी. का प्रमोचन किया गया अतः यह हमारे लिए विशेष गर्व की बात है कि यह कार्यक्रम पूरा हो गया।[8]

सोनिया गाँधी ने लोकसभा में 16 अगस्त, 2001 को प्रधानमंत्री की शिक्षा नीति का विरोध किया और कहा कि – 1998 में शिक्षा की धर्म निरपेक्ष परंपरा को राजग ने नष्ट करने के लिए एक निष्फल प्रयास किया। 31 अगस्त, 2001 को सोनिया गाँधी ने किसी भूखी शेरनी की तरह सरकार पर हमला बोल पूरे देश को अचंभित कर दिया और वाजपेयी को भी निरूत्तर कर दिया।

जिस तरह भाजपा ने बोफोर्स मामले में स्व. राजीव गाँधी को मुख्य आरोपी बनाया था और आरोप पत्र दाखिल किया था इस घटना से सोनिया गाँधी के मन में भाजपा के खिलाफ असंतोष था और 2001 में सोनिया गाँधी को भी मौका मिला और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर उसकी आलोचना की, क्योंकि उनके मन में भाजपा के कई मामले कौंध रहे थे। तहलका घोटाला जिसमें एक बेवसाइट पर कुछ रक्षा अधिकारियों और सत्तारूढ़ गठबंधन के पदाधिकारियों को रिश्वत लेते दिखाया गया था। आगरा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की आगरा शिखर वार्ता असफल हुई। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया संकट जिसमें निवेशकों ने अपनी बचत को गायब होते देखा और कई मामलों की पर्तें खुलना जिसमें अनसुलझा अयोध्या मुद्दा, किसानों और छोटे उद्योगपतियों पर विश्व व्यापार का बढ़ता प्रभाव, निवेश की प्रक्रिया और शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण।

सोनिया गाँधी ने देश में बढ़ती भुखमरी पर चिंता प्रकट की और कहा कि – भाजपा का यह दुर्भाग्य है कि वह महिलाओं को आरक्षण देने में कतरा रही है। 13 दिसम्बर, 2001 में संसद पर हुए हमले की कांग्रेस पार्टी ने निंदा की। सोनिया गाँधी ने कहा – 13 दिसम्बर, 2001 को हुए कायरतापूर्ण हमले के कारण हमारे संसदीय इतिहास में दर्ज किया जायेगा। आतंकवादियों द्वारा किया गया यह हमला

संसद भवन पर नहीं अपितु संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक और हमारे द्वारा संजोये गए उन सभी मूल्यों के प्रतीक इस भव्य संस्था पर किया गया हमला था। पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी ऐसी संस्था होने का गर्व नहीं कर सकता। कई बार जब लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया तो हमेशा ही उन प्रयासों को सैन्य कार्यवाही द्वारा कुचल दिया गया।

सोनिया गाँधी ने भाजपा सरकार तथा सभी राजनीतिक दलों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठने को कहा। उन्होंने कहा कि – 13 दिसम्बर ऐसा क्षण था जब संपूर्ण देश को मातृभाव का परिचय देते हुए एकजुट हो जाना चाहिए। एकता की भावना उत्पन्न करना सरकार की जिम्मेदारी थी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने तत्कालीन भाजपा सरकार को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की एकता को खण्डित करने की धमकी देने वाले आतंकवादियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने में सरकार का समर्थन करेगी क्योंकि हम वर्षों से आतंक का शिकार बन रहे हैं जिसकी चरम परिणति निःसंदेह 13 दिसम्बर की भयानक घटना थी अतः हमें निश्चित रूप से संगठित और कूटनीतिक आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए और देश के औचित्यपूर्ण कदम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पूर्ण समर्थन जुटाना चाहिए।[9]

सोनिया गाँधी ने जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में कुछ सवाल सत्ता पक्ष से किये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे से ऊपर उठने की लगातार कोशिशों से विपक्ष बहुत बुरी रोशनी में दिखाई दिया एवं कुछ महीनों तक तंत्र थोड़ा अधूरा नजर आया। सोनिया गाँधी ने राजद के नेता लालू प्रसाद यादव एवं वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के माध्यम से मुलायम सिंह के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश की परंतु उनके प्रयास असफल रहे क्योंकि मुलायम सिंह सोनिया गाँधी को हमेशा खतरा मानते रहे शरद पवार एवं भाजपा के संसदीय मामलों के मंत्री प्रमोद महाजन के विपरीत मुलायम सिह ने कभी सोनिया गाँधी की शक्ति को कम नहीं आंका क्योंकि मुलायम को अच्छी तरह मालूम था कि सोनिया के साथ गाँधी शब्द जुड़ा है और गाँधी शब्द देश का सबसे शक्तिशाली और राजनीति में अग्रणी शब्द है। मुलायम सिंह लगातार यही कहते रहे कि – हमें

भाजपा या बहुजन समाज पार्टी से खतरा नहीं है बल्कि हमें कांग्रेस (सोनिया गाँधी) से खतरा है क्योंकि कांग्रेस हमारा आधार खा सकती है। चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही गैर भाजपा वाले धर्मनिरपेक्ष स्थान के लिये होड़ कर रहे थे, इसलिए दोनों पार्टियां 1999 में एक साथ नहीं दिखाई दी। मुलायम सिंह यादव ने बाजपेयी का साथ दिया और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का समर्थन किया था, जिसका परिणाम था अफगानिस्तान में बमबारी। कांग्रेस एवं सोनिया गाँधी ने सरकार की आलोचना करने का विकल्प चुना।

विपक्षी नेताओं में सोनिया गाँधी के हरकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु से विशेष मित्रतापूर्ण संबंध थे जबकि लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गाँधी को हमेशा ही पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाया और उन्होंने अन्य विपक्षी नेताओं को भी सोनिया गाँधी के पक्ष में करने की कोशिश की।

सोनिया गाँधी जब लोकसभा में चुनकर पहुंची और कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें अपना कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना तो उस समय सोनिया गाँधी में अनुभव एवं विश्वास की कमी थी जबकि मेरा मानना है कि सोनिया गाँधी के पास अनुभव तो था परंतु उनके संकोची स्वभाव के कारण उन्हें नेताओं ने अनुभवहीन करार दिया। सोनिया गाँधी शुरू में सत्ता पक्ष (भाजपा) के सांसदों का निशाना बन गई क्योंकि वे कम बोलती थीं जिससे कांग्रेसी सांसदों को सत्ता पक्ष के सामने अपमानित सा होना महसूस होता था परंतु शीघ्र ही सोनिया गाँधी ने हिसाब बराबर करने की तैयारी की। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु नीति के मामले में पार्टी के विचारों पर कांग्रेस को ताना मारा तो नेता प्रतिपक्ष सोनिया गाँधी चुप रहीं जिस कारण कांग्रेस सांसदों को काफी निराशा हुई।

सोनिया गाँधी ने अपने सांसदों की अपेक्षाओं को भांप लिया और उन्होंने परमाणु विषय के विशेषज्ञों को बुलाया जिनमें वह लोग भी शामिल थे जो कांग्रेस के थिंक टेंक में शामिल नहीं थे। उन्होंने इस विषय की बारीकियों को समझा और पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री पर इस मामले को लेकर हमला बोला। लोकसभा में 12 मार्च, 2001 को सोनिया गाँधी ने बाजपेयी से पूछा – क्या परमाणु नीति में स्पष्ट दूरदृष्टि है? पिछले सत्र में मान्नीय प्रधानमंत्री ने मुझे चुनौती देते हुए हंसी

का माहौल बनाया था कि परमाणु नीति पर कांग्रेस के विचार क्या हैं? मैं प्रधानमंत्री की उसी हंसी को लेकर उनसे अप्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि आखिरकार वे पिछले पचास साल के सर्वाधिक वाकपटु सांसदों में से एक हैं। सोनिया गाँधी ने यहां भी अपनी नारी सभ्यता का परिचय दिया उन्होंने कहा कि – श्रीमान् हम राष्ट्रीय सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं कि संसद के सदन में हंसी मजाक से इसे तय नहीं करना चाहते। इसलिए मैं यह सवाल प्रधानमंत्री की तरफ वापिस उछालना चाहती हूँ कि एनडीए सरकार की परमाणु नीति क्या है ? उन्होंने कहा – पिछले 18 महीनों से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंडल की अनुशंसायें धूल खा रही हैं। तीन छोटे शब्दों 'न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध' को नीति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनका नीति के रूप में विस्तार किया जाना चाहिए जब ऐसा किया जायेगा तो जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे और यदि संभव हुआ तो उसका समर्थन भी करेंगे। परंतु हम इस समय किस तरह समर्थन दे सकते हैं ? हम जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के कारण ऐसी नीति का समर्थन नहीं कर सकते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है।[10]

सन् 2001 में विपक्ष के नेता की हैसियत से सोनिया गाँधी ने अमेरिका की पहली राजनैतिक यात्रा की। उपराष्ट्रपति डिक चेनी और बुश प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ उनकी व्यक्तिगत मुख्य मुलाकातें हुई। 2001 में एड्स H.I.V. पर राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा को संबोधित किया। सोनिया गाँधी को ऊपर उठाये जाने के पीछे राजनैतिक सौदा था कि वे तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणनन् को दिये गये मेमोरेंडम से बाजपेयी का नाम वापस ले लेगी जिसमें तहलका भंडाफोड़ के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा गया था। सोनिया गाँधी ने नाम वापिस नहीं लिया। सोनिया गाँधी की सफल अमेरिका यात्रा में सरकार और भाजपा के सांसद दीनानाथ मिश्रा भी शामिल थे जिन्होंने सोनिया गाँधी पर कई अजीबोगरीब आरोप लगाये थे। विसंगति यह थी कि मिश्रा की पार्टी भाजपा ने ही सोनिया गाँधी को जून 2001 में राष्ट्र संघ के एड्स सम्मेलन में एक अरब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। उन्होंने गरिमा के साथ सफलता पाई थी। सोनिया गाँधी की कार्यशैली कांग्रेस गलियारों में गहन चर्चा का विषय बन गई।[11]

25 मार्च, 2002 को संसद के संयुक्त सत्र में सोनिया गाँधी ने विपक्ष की नेता के रूप में राजग (भाजपा) सरकार को नई चुनौती दी। पोटा पर बहस करते हुए उन्होंने कहा – पोटा के रूप में सरकार के हाथ में एक दमनकारी हथियार है। इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार इसका इस्तेमाल अपने राजनैतिक विरोधियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, जाति समूहों, कमजोर वर्गों, और ट्रेड यूनियनों का दमन करने में करेगी।

सोनिया गाँधी ने आरोप लगाया कि बाजपेयी संघ परिवार के दबाव में आकर यह अध्यादेश (पोटा) पारित करवा रहे हैं। बाजपेयी सोनिया गाँधी की इस बात का बुरा मान गये। उत्तेजित बाजपेयी सोनिया गाँधी पर प्रबल आक्रमण करने लगे उन्होंने एक महिला के खिलाफ जिस शब्द शैली का प्रयोग किया उससे सभी बुद्धिजीवी विचलित हो उठे जबकि सोनिया गाँधी ने हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए बाजपेयी का आदर किया। यही वह मौका था जिसने इस कालखण्ड के सबसे मर्यादित सांसद कहे जाने वाले बाजपेयी को भी तिलमिलाने को मजबूर कर दिया था।[12]

15 मार्च, 2002 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया कि – साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और अपने संविधान के सिद्धांतों का पालन करना, हमारे राष्ट्र की विशेषताओं का मूल आधार है। 15 मार्च, 2002 को सोनिया गाँधी ने संसद में सर्वप्रथम अहिंसा के प्रतीक महात्मा की धरा गुजरात के गोधरा में हुए नरसंहार और तदन्तर अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत तथा अन्य स्थानों पर हुए नरसंहार पर अपनी पीड़ा और संताप व्यक्त करते हुए कहा कि – गुजरात की अभिघाती घटनाओं से सभ्य मानव समाज की प्रतिष्ठा कम हुई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अहमदाबाद में निर्दोष लोगों की हत्या, जिंदा बचे भयभीत लोगों, नष्ट की गई संपत्ति और ऐसे मां–बाप को देखा था जिसके सामने उसकी जवान बेटी की इज्जत लूट ली गई यह घृणास्पद कार्य गुजरात में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए जिसकी पूरे विश्व ने निंदा की। छोटे–छोटे बच्चों और महिलाओं को रेलगाड़ी में जिंदा जला दिया गया यह क्रूरता राज्य सरकार की आंखों के सामने की गई। जिसकी सहापराधिता पूरी तरह उजागर हो गई। सोनिया

गाँधी ने स्पष्ट कहा कि इस सबके पीछे भाजपा का हाथ था प्रधानमंत्री वाजपेयी को यह बात ठीक नहीं लगी।

सोनिया गाँधी ने 2002 में संसद में प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुये कहा कि विश्व हिन्दू परिषद की कार्यवाही से अयोध्या में उत्पन्न स्थिति से निपटने में केन्द्र सरकार की ओर से जो कृत्य हुए वे शर्मनाक हैं। अयोध्या में बढ़ते तनाव के संबंध में चेतावनियों के बावजूद इसे बढ़ने दिया गया। तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया जिनमें सच्चाई लेशमात्र भी नहीं थी सरकार के एजेंडा की द्वैधता से देश की जनता को आघात पहुंचा। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार प्रस्तावित विश्व हिन्दू परिषद की योजना के संबध में तटस्थ हैं वास्तव में प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरी तरह अस्पष्ट था। सोनिया गाँधी ने कहा – कि 11 मार्च, 2002 को राज्य सरकारों ने रेल से अयोध्या जाने वाले कारसेवकों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने को कहा गया। फिर ऐसा "यू टर्न" अर्थात् एकदम विपरीत रवैया क्यों अपनाया गया? और "यू टर्न" क्यों लिया गया। शायद इसका जबाब प्रधानमंत्री को 7 मार्च, 2002 भाजपा संसद सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र में दिया गया, पत्र में इन सांसदों ने उनको (वाजपेयी) और उनकी सरकार को धमकी दी थी कि यदि प्रधानमंत्री ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिससे प्रधानमंत्री को अपना मन बदलना पड़ा और सरकार को महाअधिवक्ता से मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश देना पड़ा, जैसा हस्तक्षेप उन्होंने उच्चतम न्यायालय में किया था। उन्होंने कहा कि – हम ऐसी सरकार के बारे में क्या सोचें? जिसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है जो विरोधाभासों से घिरी हुई है तथा जो राष्ट्रीय हितों पर गुटों के दबाव को महत्व देती है एवं साम्प्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेक देती है।

सुरक्षा के मामलें में भी भाजपा सरकार ने लापरवाही पूर्ण कार्य किया। 1999 में हुए कारगिल युद्ध पर सुब्रमणियम रिपोर्ट के बारे में भाजपा ने न तो कार्यवाही आगे बढ़ाई और न ही सदन को सुब्रमणियम रिपोर्ट के बारे में बताया गया क्योंकि रक्षा मंत्रालय उस समय तक घपले–घोटाले में व्यस्त था।[13]

17 मई, 2002 को नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के रक्षा मंत्रालय की कलई खोलते हुए स्पष्ट किया कि यह सरकार जनता और देश की सर्वोच्च संस्था की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हुए हमला और अक्टूबर, 2001 में जम्मू–कश्मीर विधानसभा पर हुए हमले की निंदा की। सोनिया गाँधी ने सरकार से मांग की, कि इस तरह की घटनाओं पर पाबंदी लगाये और विद्रोही आतंकवादियों को चुन–चुन कर मार गिराये।

18 अगस्त, 2003 को कांग्रेस संसदीय दल की नेता एवं 1999 में दूसरी बार भाजपा के सत्ता में आने के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि – देश में इस प्रकार की निरंकुशता में खतरा अंतर्निहित है, और यह खतरा हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के लिए खतरा है। यह स्वतंत्रता के न्याय के लिए व पूर्वजों के आदर्श के लिए खतरा है। सन् 1998–2003 तक देश में जिस तरह के उपद्रव हुए इन उपद्रवों एवं देश में जगह–जगह आतंकवादी हमलों के अलावा आर.एस.एस. की भूमिका को लेकर सोनिया गाँधी ने भाजपा सरकार की निंदा की एवं कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा करने में नाकाम सिद्ध हुई।

सन् 2003 में लोकसभा में सरकार की विफलताओं को गिनाया एवं सरकार की नौ विफलताओं पर अविश्वास प्रस्ताव रखा, उन्होंने भाजपा सरकार पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया, भाजपा सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया क्योंकि कुछ ऐसी घटनायें घटी जिसके बारे में कभी सरकार ने भी नहीं सोचा था, सामाजिक सदभाव को जान–बूझकर बिगाड़ने का आरोप (भाजपा) पर लगाया क्योंकि गुजरात जैसे कार्य सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जान बूझकर किये गये थे, भाजपा सरकार पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गाँधी ने शैक्षणिक प्रणाली की धर्मनिरपेक्ष विशेषता के साथ छेड़–छाड़ का आरोप लगाया, सरकार पर सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में सत्यनिष्ठा नष्ट करने का आरोप लगाया क्योंकि राजग सरकार के दौरान देश में भ्रष्टाचार और नौकरशाही को बढ़ावा मिला। 2003 में सोनिया गाँधी ने सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने और सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर निजीकरण को बढ़ावा देने का

दोष मढ़ा, भाजपा पर किसानों और खेत मजदूरों को भारी मुसीबतों में डालने का आरोप लगाया, संसदीय प्रजातंत्र की प्रमुख संस्थाओं की प्रतिष्ठा को कम करने का आरोप लगाया, सोनिया गाँधी ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी पर विदेश नीति की स्वतंत्रता की खुल्लम–खुल्ला उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

सोनिया गाँधी द्वारा जो आरोप भाजपा सरकार पर लगाये गये वह उतने ही व्यापक थे जितनी इस सरकार की विफलताएं। नेता प्रतिपक्ष से सरकार पर एक आरोप और लगाया जो उन सभी आरोपों के समान नहीं था सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु आवंटित 23,197 करोड़ रूपये खर्च नहीं किए गये।

सोनिया गाँधी ने लोकसभा में सरकार की इन जन विरोधी नीतियों का विरोध किया।[14] 18 अगस्त 2003 को सोनिया गाँधी ने लोकसभा में कहा कि – कुछ महीने पहले जब मैंने कहा था कि भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार बहुत ही भ्रष्ट है तो मैं समझती थी कि मेरी बात स्पष्टतः उतनी ही सही हो पाएगी और हमें ताज कारिडोर स्केण्डल से जूझना पड़ेगा। सब लोग जानते है कि क्या हो रहा है। दरअसल जब तक मामला उजागर नहीं हुआ तब तक सब कुछ गुप–चुप तरीके से चलता रहा।

सोनिया गाँधी ने ताज स्कैण्डल मामले के ठीक पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की जमीन घोटाले का भंडाफोड़ किया इसमें न्यायिक आदेशों तक की सरकार ने अनदेखी की। इसके बाद उन्होंने और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते हुए सरकार की पोल खोली। जिसमें पेट्रोल पंप आवंटन घोटाला, शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली में भूमि घोटाला कर महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थित प्लांट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.), विश्व हिन्दू परिषद (बी.एच.पी.) और इनसे जुड़े लोगों को कम दर पर उपलब्ध कराये, भाजपा सरकार के दौरान रोजगार की बहुत ही निराशाजनक स्थिति हुई प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियाँ देने का वायदा देश की जनता से किया था परंतु वह अपना वायदा नहीं निभा पाये, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान आर्थिक विकास की औसत दर प्रतिवर्ष 6.7 प्रतिशत थी वह घटकर 4.3 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि सरकार ने घोषणा

की थी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा था।

सन् 1990 के दशक में रोजगार सृजन की दर प्रतिवर्ष 2.7 प्रतिशत थी। जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में घटकर प्रतिवर्ष केवल 1 प्रतिशत रह गई। सोनिया गाँधी ने लोकसभा में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार के दौरान ही स्वर्णजयंती स्वरोजगार ग्रामीण योजना विफल साबित हुई सरकार ने सन् 2000 में एक राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी किन्तु इस नीति पर सरकार ने कभी चर्चा नहीं की।

18 अगस्त, 2003 को नेता प्रतिपक्ष सोनिया गाँधी ने संसद में राजग सरकार को कटघरे में खड़ा कर राजग सरकार को चौंका दिया। उन्होंने सरकार पर अयोध्या मुद्दे और बाबरी–मस्जिद विध्वंस के मामले में सी.बी.आई. के घोर राजनीतिकरण पर आपत्ति जताई साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर लगे आक्षेप की निंदा की एवं राजग सरकार की विदेश नीति की कटु आलोचना करते हुए कहा कि – राजग शासन के दौरान पिछले 5 वर्षों में सार्क का महत्व कम किया गया एवं 1972 के शिमला समझौते को भी भुलाने की कोशिश की गई, एवं पंचशील सिद्धांत का भी सरकार के मुखिया ने मजाक उड़ाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि भारतीय विदेश नीति अपने रास्ते से भटक रही है।[15]

सोनिया गाँधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में अपना अंतिम भाषण 4 फरवरी, 2004 को दिया। उन्होंने 13वीं लोकसभा की आखिरी चर्चा में कहा कि – सरकार ने संवैधानिक मूल्यों और संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन किया। भाजपा का सबसे बड़ा योगदान घोटालों का रहा चाहे वह रक्षा संबंधी हो, पेट्रोल पम्प संबंधी हो, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की जमीन आवंटन, शेयर बाजार, यू.टी.आई., हुडको, तहलका का मामला रहा हो या जूदेव वीडियो टेप मामला रहा हो। रक्षा आधुनिकीकरण (Defense Modernization) के लिए रखा गया हजारों करोड़ रूपये खर्च ही नहीं किया गया इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हुआ सरकार ने रक्षा सौदे करने में पारदर्शिता से काम नहीं किया।

भाजपा सरकार ने सामाजिक सद्भाव के माहौल को बुरी तरह से नष्ट कर दिया सरकार ने देश में साम्प्रदायिकता और नफरत फैलाने वाले संगठनों की हर तरह से मदद की। राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हुए अत्याचारों का सबसे ज्यादा निशाना दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं बनी। सरकार ने कांग्रेस के समर्थन के बाद भी महिला आरक्षण बिल पास नही किया। इसके विपरीत कांग्रेस के कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये। अनुसंधान अभिकरणों (Investigating Agencies) और जाँच आयोगों (Commissions of Enquiry) को जान बूझकर अपंग बनाया गया।

सोनिया गाँधी ने 4 फरवरी, 2004 को संसद में कहा कि – राजग सरकार ने न केवल शिक्षा संस्थाओं को ही बर्बाद किया गया बल्कि सी.ए.जी. सी.बी.सी. इलेक्शन कमीशन और मानव अधिकार आयोग (Human Rights Commission) जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं बख्शा गया, एवं अनुसंधान अभिकरणों (Investigating Agecies) और जाँच आयोगों को जान–बूझकर अपंग बनाया गया, जबकि सी.बी.आई. अयोध्या के मामले में अपील तक दायर नहीं कर पाई और लिब्राहन आयोग से उसका जाँच अधिकारी तक हटा दिया गया। गुजरात का कत्लेआम हो या फिर घोटालों का बोलबाला सब कुछ राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान ही संभव हुआ है। सोनिया गाँधी ने कहा कि – इस सरकार (राजग) ने अपनी खामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस की विरासत को दोष दिया है, और बार–बार कांग्रेस की विरासत को दोष दे रहे हैं।[16]